



उत्तराखण्ड शासन

बजट एक दृष्टि में

2026-27

उत्तराखण्ड सरकार



मार्च 2026

बजट का सार (वित्तीय वर्ष 2026 - 2027)



करोड़ रुपये में/ in crore

क्र. स.	विषय (subject)	वास्तविक आँकड़े Actuals 2024-25	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-26	पुनरीक्षित अनुमान Revised Estimates 2025-26	बजट अनुमान Budget Estimates 2026-27
1.	राजस्व प्राप्तियाँ (Revenue Receipts)	51473.34	62540.54	62639.45	67525.77
2.	कर राजस्व* (Non-Tax Revenue)	35266.08	39917.74	39253.44	43327.43
3.	करेक्टर राजस्व** (Non-Tax Revenue)	16207.26	22622.80	23386.01	24198.34
4.	पूँजीगत प्राप्तियाँ (Capital Receipts)	39745.20	38494.21	39576.36	42617.35
5.	ऋणों की वसूलियाँ (Recovery of Loans)	36.69	24.21	26.36	27.35
6.	उधार एवं अग्रिम की वसूली (Recovery of Loans & Advances)	39708.51	38470.00	39550.00	42590.00
7.	जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक से अर्धोपाय अग्रिम (of which Ways and Means Advance from R.B.I)	25904.74	19500.00	19500.00	21000.00
8.	कुल प्राप्तियाँ (1+4) (Total Receipts)	91218.54	101034.75	102215.81	110143.12
9.	राजस्व व्यय (Revenue Expenditure)	50015.58	59954.65	60178.38	64989.44
10.	ब्याज अदायगियाँ (Interest Payments)	5575.00	6990.14	6625.50	7929.40
11.	पूँजीगत व्यय जिसमें (Capital Expenditure of which)	40790.64	41220.68	41432.66	46713.77
12.	पूँजीगत परिव्यय # (Capital Outlay #)	11105.50	14763.13	14883.35	18152.73
13.	ऋणों की अदायगियाँ (Loan Payments)	28994.14	26005.66	26005.62	28160.63
14.	जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक से अर्धोपाय अग्रिम का प्रतिदान (of which repayment of Ways and Means Advance from R.B.I)	25072.96	19500.00	19500.00	21000.00
15.	ऋण और अग्रिम (Loans & Advances)	691.00	451.89	543.69	400.41
16.	कुल व्यय (Total Expenditure)(9+11)	90806.22	101175.33	101611.04	111703.21
17.	राजस्व अधिशेष (Revenue Surplus)(1-9)	1457.76	2585.89	2461.07	2536.33
18.	राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit Excl. SASCI)###	10302.06	12604.92	10639.62	12579.70
19.	प्रारंभिक घाटा (Primary Deficit) (18-10)	4727.06	5614.78	4014.12	4650.30

* इसमें राज्य का स्वयं का कर राजस्व एवं केन्द्रीय करों में राज्यांश सम्मिलित है। (It Includes State Tax Revenue and Share of Central Taxes)

** इसमें राज्य का करेक्टर राजस्व एवं केन्द्र से प्राप्त अनुदान सम्मिलित है। (It Includes State Non-Tax Revenue and Grants from GOI)

इसमें एसएएससीआई एवं घटाये वापसी सम्मिलित है। (It Includes SASCI & Deduct Refund)

इसमें एसएएससीआई एवं घटाये वापसी सम्मिलित नहीं है। (It Excludes SASCI & Deduct Refund)

बजट की विशेषताएं



नया परिवेश

केदार (KEDAR)

- K - कौशल विकास
- E - इकालॉजी संवर्धन
- D - धरोहर संरक्षण
- A - अवसंरचना निर्माण
- R - रिवर्स माइग्रेशन

मानस (MANAS)

- M - मंगलकारी
- A - अवसरयुक्त
- N - नवोन्मेशी
- A - आध्यात्मिक
- S - सांस्कृतिक गतिविधियां

बजट का मुख्य बिन्दु



SANTULAN (संतुलन)



संतुलन (SANTULAN)



समावेशी विकास (S)

समावेशी विकास के द्योतक गरीब कल्याण, महिला कल्याण एवं बाल विकास को समर्पित योजनाएं:-

- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में समग्र रूप से लगभग रु0 1327.73 करोड़
- अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना हेतु रु0 600.00 करोड़
- सक्षम आंगनबाडी एण्ड पोषण 2.0 योजना हेतु समग्र रूप से लगभग रु0 598.33 करोड़
- ई0डब्ल्यू0एस0 आवासों हेतु अनुदान के अन्तर्गत रु0 25.00 करोड़
- राज्य खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत रु0 25.00 करोड़
- प्रधानमंत्री पोषण मिशन हेतु समग्र रूप से लगभग रु0 149.45 करोड़
- मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना हेतु रु0 30.00 करोड़
- मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना हेतु रु0 15.00 करोड़
- राज्य में प्रसूता के लिए ईजा-बोर्ड शगुन योजना हेतु समग्र रूप से लगभग रु0 14.13 करोड़
- मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना हेतु लगभग रु0 13.44 करोड़
- मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेतु रु0 15.00 करोड़
- मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि रु0 8.00 करोड़

संतुलन (SANTULAN)



आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड (A)

आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण से कृषि, उद्योग एवं पर्यटन सैक्टर से संबंधित योजनाएं:-

- पशुपालन विभाग के अन्तर्गत स्वरोजगार परक व लाभार्थीपरक योजना हेतु लगभग रु0 42.02 करोड़
- समग्र रूप से मिशन एप्पल के लिए रु0 42.00 करोड़
- ट्राउट प्रोत्साहन योजना हेतु लगभग रु0 39.90 करोड़
- उच्च मूल्य वाले फलों (कीवी, ड्रेगन फ्रूट आदि) के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लगभग रु0 30.70 करोड़
- राज्य में चाय विकास योजना के लिए लगभग रु0 25.93 करोड़
- सगन्ध पौधा केन्द्र को अनुदान एवं सगन्ध पौधों के क्लस्टर विकास के लिए लगभग रु0 24.75 करोड़
- फसलों की सुरक्षा के लिए घेरबाड़ हेतु रु0 20.00 करोड़
- प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता योजना के लिए रु0 75.00 करोड़
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए रु0 60.00 करोड़
- प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप और इंटर्प्रीनियोरशिप के लिए रु0 30.00 करोड़
- स्टार्ट अप वेंचर फंड हेतु रु0 25.00 करोड़
- मेगा इंडस्ट्रियल एवं मेगा टेक्सटाईल नीति के तहत अनुदान के लिए रु0 25.00 करोड़
- इको टूरिज्म गतिविधियों के लिए समग्र रूप से रु0 18.50 करोड़
- हरिद्वार गंगा कॉरिडोर परियोजना रु0 10.00 करोड़
- ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना रु0 10.00 करोड़
- सरयू एवं अन्य रिवर फ्रंट योजनाओं हेतु रु0 10.00 करोड़

संतुलन (SANTULAN)



नई सोच (N)

- संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान हेतु रु0 28.00 करोड़
- खनन सर्विलांश योजना के अन्तर्गत रु0 24.50 करोड़
- विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत छात्रवृत्ति हेतु रु0 15.00 करोड़
- उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत छात्रवृत्ति हेतु रु0 15.00 करोड़
- खेल विभाग के अंतर्गत छात्रवृत्ति हेतु लगभग रु0 13.50 करोड़
- उद्यमिता, कौशल एवं नवाचार योजना के अन्तर्गत लगभग रु0 7.11 करोड़
- राजकीय महाविद्यालयों में ई-ग्रंथालय की स्थापना हेतु रु0 7.00 करोड़
- "लैब ऑन व्हील्स" योजना के लिए रु0 4.00 करोड़
- राज्य डॉटा सेंटर सुदृढीकरण के लिए समग्र रूप से रु0 65.00 करोड़
- सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना के अन्तर्गत लगभग रु0 47.50 करोड़
- पहाड़ी शहर में नगर निकायों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु रु0 30.00 करोड़
- साइबर सिक्योरिटी के क्रियान्वयन हेतु रु0 15.00 करोड़
- इमरजिंग टेक्नोलॉजी एवं ए0आई0 (सी0ओ0ई0) के क्रियान्वयन हेतु लगभग रु0 11.50 करोड़
- शहरी क्षेत्रों में पैदल मार्ग अवसंरचना के अन्तर्गत रु0 10.00 करोड़
- विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अन्तर्गत रु0 6.71 करोड़
- पैक्स के कम्प्यूटरीकरण हेतु लगभग रु0 5.67 करोड़
- जनपदों में केंद्रीकृत रिकॉर्ड रूम के अन्तर्गत रु0 10.00 करोड़
- यूनीफार्म सिविल कोड के अन्तर्गत रुपये पांच करोड़ रु0 5.00 करोड़

संतुलन (SANTULAN)

तीव्र विकास (T)

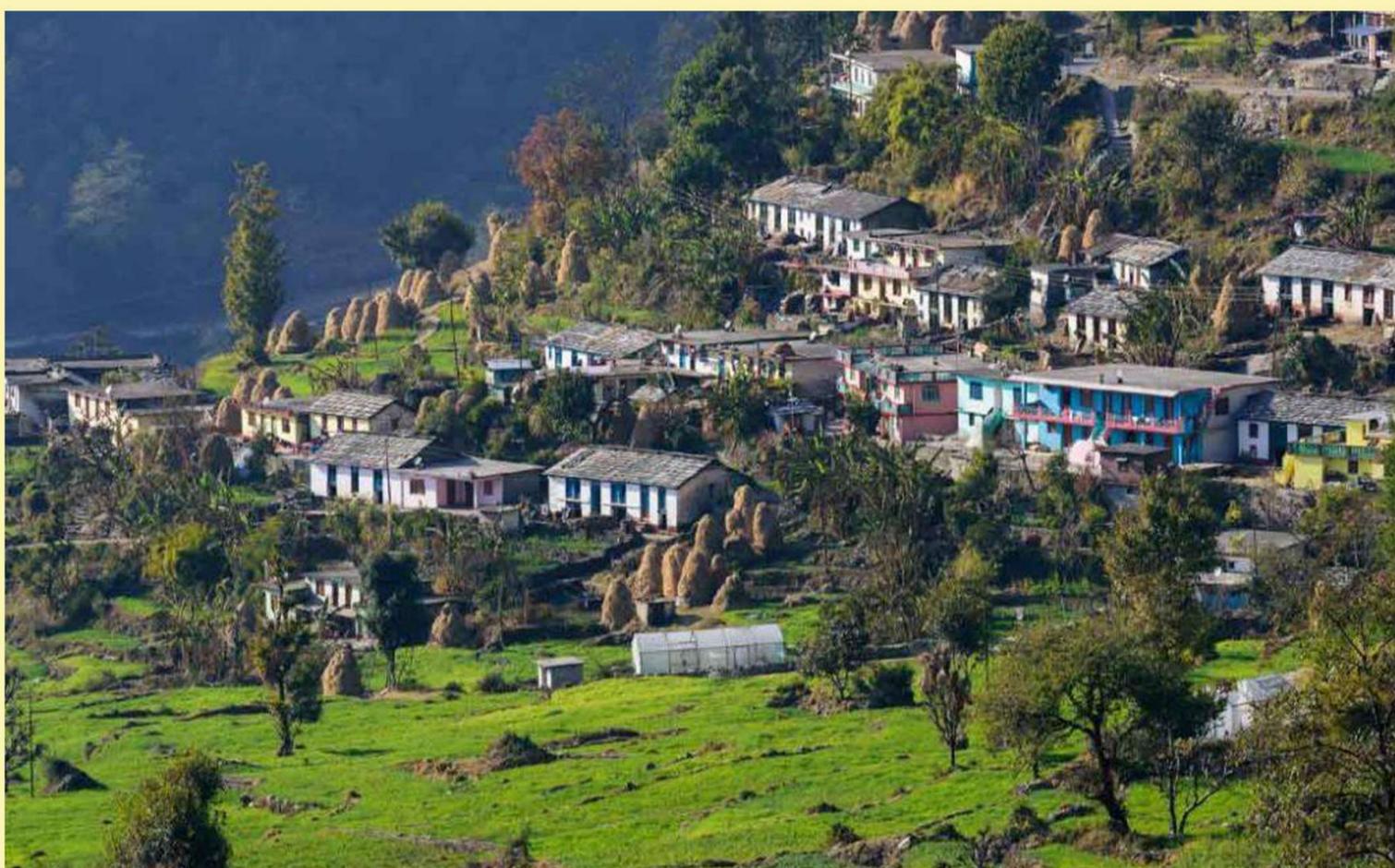
- पीएमजीएसवाई योजना के अन्तर्गत पूंजीगत मद में रु० 1050.00 करोड़
- गढ़ा मुक्त सड़क अभियान हेतु रु० 400.00 करोड़
- नागरिक उड्यन विभाग के अन्तर्गत समग्र रूप से पूंजीगत मद में लगभग रु० 52.50 करोड़
- नंदा देवी राजजात यात्रा के लिए रु० 25.00 करोड़



संतुलन (SANTULAN)

उन्नत शहर एवं गाँव का विकास (U)

- विकसित भारत -जी राम जी हेतु समग्र रूप से लगभग रु0 705.25 करोड़
- ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत समग्र रूप से पूंजीगत मद में रु0 1642.20 करोड़
- वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम हेतु रु0 40.00 करोड़
- शहरी निकायों हेतु समग्र रूप से रुपये रु0 1814.00 करोड़ एवं पंचायती राज संस्थाओं हेतु रु0 1491.00 करोड़
- आवास विकास विभाग के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास आदि हेतु रु0 130.00 करोड़
- नगरीय अवस्थापना के सुदृढीकरण हेतु रु0 60.00 करोड़



संतुलन (SANTULAN)



लोक सहभागिता (L)

- राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढीकरण/आई०टी०डी०ए० को अनुदान-
रु० 25.00 करोड़
- राज्य डाटा सेंटर सुदृढीकरण- रु० 40.00 करोड़
- ए०आई० मिशन के क्रियान्वयन हेतु- रु० 13.00 करोड़
- विज्ञान केंद्र चंपावत- रु० 20.00 करोड़

संतुलन (SANTULAN)



आर्थिक शक्ति (A)

- रिस्पना बिंदाल की एलिवेटेड यूटिलिटी शिफ्टिंग- रु0 350.00 करोड़
- टिहरी रिंग रोड परियोजना- रु0 10.00 करोड़
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना- रु0 1050.00 करोड़
- स्टार्ट अप वेंचर फंड हेतु- रु0 25.00 करोड़
- प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता योजना के लिए- रु0 75.00 करोड़
- मेगा इंडस्ट्रियल एवं मेगा टेक्सटाईल नीति के तहत अनुदान के लिए- रु0 25.00 करोड़
- इको टूरिज्म गतिविधियों के लिए समग्र रूप से- रु0 18.50 करोड़
- प्रमोशन ऑफ इंवेस्टमेंट, स्टार्टअप और इंटरप्रीनियोरशिप के लिए- रु0 30.00 करोड़
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए- रु0 60.00 करोड़

संतुलन (SANTULAN)



न्यायपूर्ण व्यवस्था (N)

- पुलिस आवास हेतु - रु0 100.00 करोड़
- इण्डिया रिजर्व वाहिनी की स्थापना- रु0 10.00 करोड़
- स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स- रु0 10.00 करोड़
- आन्तरिक सुरक्षा हेतु केन्द्रीय पुलिस बल आदि को भुगतान- रु0 2.50 करोड़
- जेलों का निर्माण/ भूमि क्रय- रु0 25.00 करोड़
- कारागार हेतु आवासीय भवनों का निर्माण- रु0 10.00 करोड़
- उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी- रु0 6.96 करोड़
- टेप एंड पोक्सो एक्ट के लंबित प्रकरणों हेतु फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट - रु0 3.42 करोड़



प्रमुख आर्थिक बिन्दु (बजट 2026-27)

₹ 111703.21 करोड़ बजट का आकार
(2025-26 के सापेक्ष 10.41% वृद्धि)

व्यय

राजस्व व्यय: ₹ 64989.44 करोड़
पूंजीगत व्यय: ₹ 46713.77 करोड़
पूंजीगत परिव्यय: ₹ 18152.73 करोड़



प्राप्तियाँ

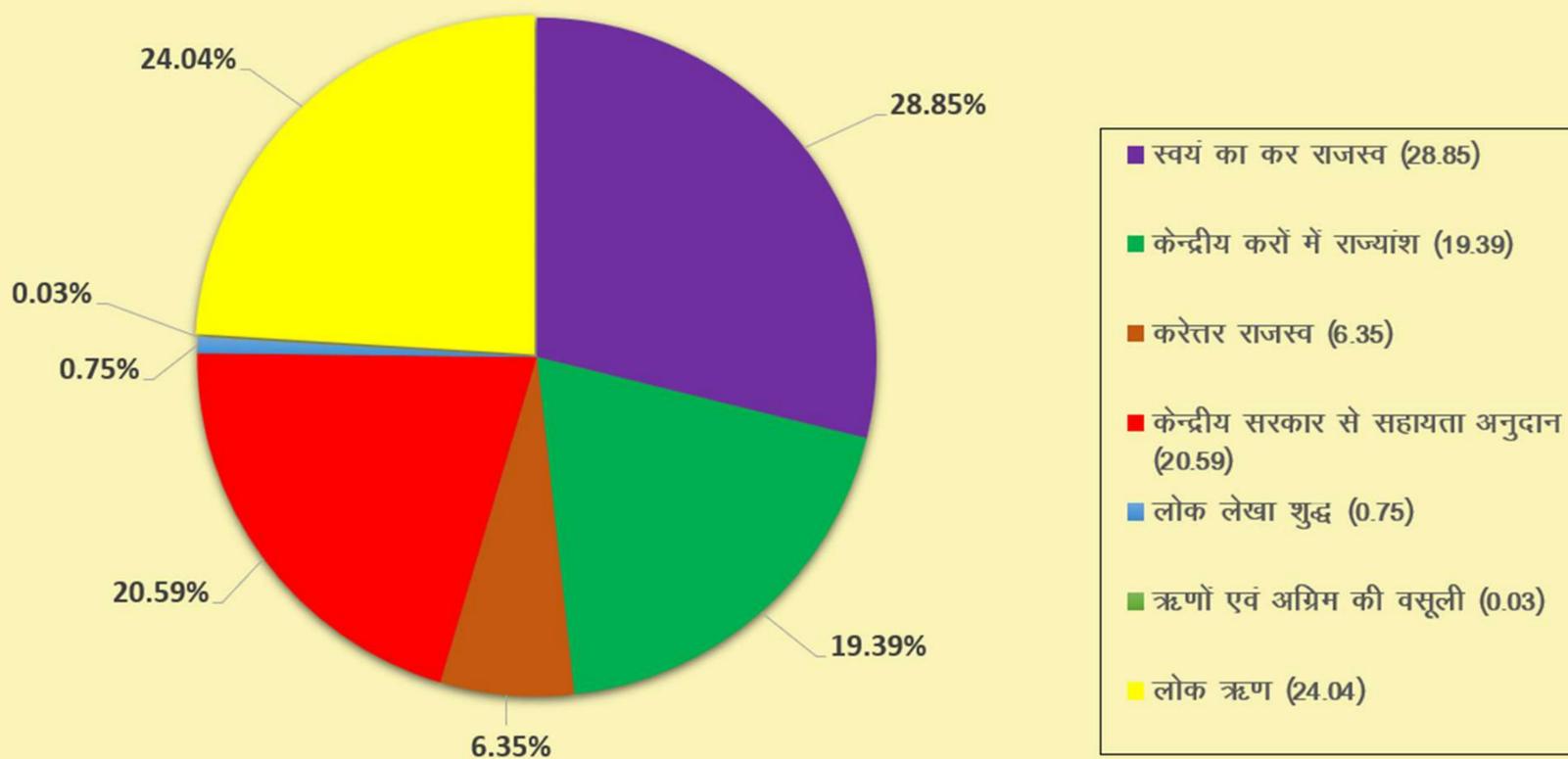
कुल प्राप्तियाँ: ₹ 110143.12 करोड़
राजस्व प्राप्तियाँ: ₹ 67525.77 करोड़
पूंजीगत प्राप्तियाँ: ₹ 42617.35 करोड़



निधि का प्रवाह

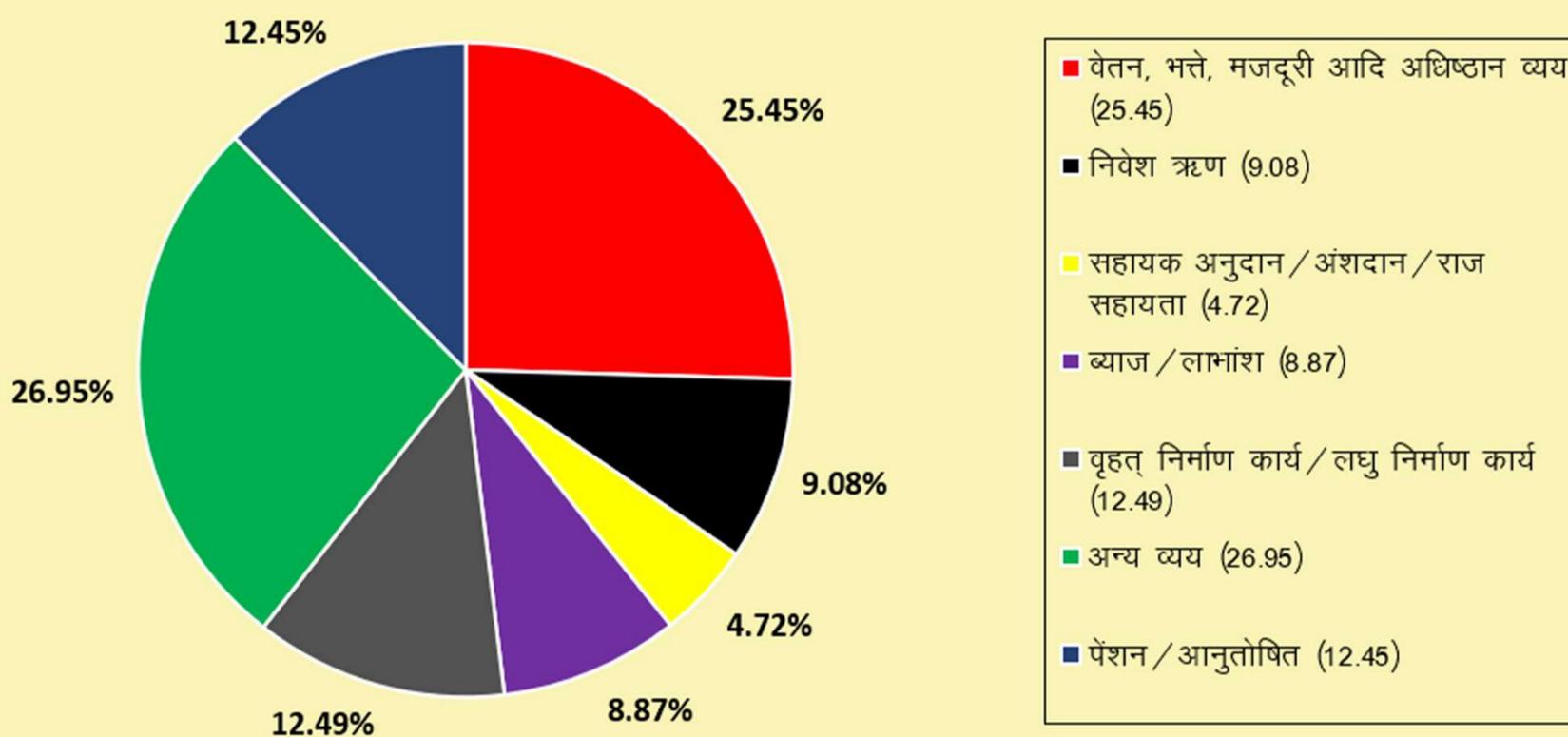
रुपया आता है

रुपया आता है (अर्थोपाय अग्रिम की धनराशि को छोड़कर)



रुपया जाता है

रुपया जाता है (अर्थोपाय अग्रिम की धनराशि को छोड़कर)



FRBM अधिनियम का अनुपालन

- ✓ राजस्व आधिक्य - **हाँ**
- ✓ राजकोषीय घाटा, (जी०एस०डी०पी० के प्रतिशत में)
3 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत - **हाँ**
- ✓ लोक ऋण (जी०एस०डी०पी० के प्रतिशत में)
32.50 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत - **हाँ**



प्रमुख पूंजीगत योजनाएं



- माध्यमिक शिक्षा विभाग - ₹ 542.84 करोड़
- उच्च शिक्षा विभाग - ₹ 146.30 करोड़
- तकनीकी शिक्षा विभाग - ₹ 98.50 करोड़
- खेल विभाग - ₹ 69.94 करोड़
- कला एवं संस्कृति विभाग - ₹ 9.90 करोड़
- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग - ₹ 195.46 करोड़
- चिकित्सा शिक्षा विभाग - ₹ 126.37 करोड़
- पेयजल विभाग - ₹ 1827.91 करोड़
- आवास - ₹ 291.00 करोड़
- शहरी विकास विभाग - ₹ 1401.85 करोड़
- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग - ₹ 98.45 करोड़
- ग्रामीण विकास विभाग - ₹ 1642.20 करोड़
- ऊर्जा विभाग - ₹ 1609.43 करोड़
- लोक निर्माण विभाग - ₹ 2501.91 करोड़
- सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग - ₹ 86.00 करोड़
- नागरिक उड्डयन विभाग - ₹ 52.50 करोड़
- परिवहन विभाग - ₹ 67.45 करोड़
- वन विभाग - ₹ 131.68 करोड़
- पशुपालन विभाग - ₹ 47.00 करोड़
- मत्स्य विकास विभाग - ₹ 30.13 करोड़
- औद्योगिक विकास विभाग - ₹ 74.00 करोड़

नई योजनाएं



- कुम्भ मेला हेतु भारत सरकार से अवस्थापना के लिए समग्र रूप से रु0 1027.00 करोड़
- विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) हेतु समग्र रूप से रु0 705.25 करोड़
- निर्भया फण्ड के लिए रु0 112.02 करोड़
- पर्यटन विकास हेतु अवस्थापना निर्माण के लिए रु0 100.00 करोड़
- कोलोनाइजेशन प्रोत्साहन हेतु अवस्थापना निर्माण हेतु रु0 25.00 करोड़
- हरिद्वार गंगा कॉरिडोर परियोजना हेतु रु0 10.00 करोड़
- ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना हेतु रु0 10.00 करोड़
- साईबर सिक्योरिटी के क्रियान्वयन हेतु रु0 15.00 करोड़
- इमरजिंग टेक्नोलॉजी एवं ए0आई0 के क्रियान्वयन हेतु रु0 10.50 करोड़
- महक क्रान्ति हेतु रु0 10.00 करोड़
- स्पिरिचुअल इकोनोमिक ज़ोन के विकास हेतु रु0 10.00 करोड़
- हाउस ऑफ़ हिमालयाज हेतु रु0 5.00 करोड़
- उत्तराखण्ड एवं भारत दर्शन हेतु रु0 4.50 करोड़
- सरयू एवं अन्य रिवर फ्रंट योजनाओं हेतु रु0 10.00 करोड़
- आपदा सखी हेतु रु0 2.00 करोड़
- ग्राम प्रहरी हेतु रु0 5.00 करोड़
- नशा मुक्ति केन्द्र हेतु रु0 4.50 करोड़
- पुस्तकालय निर्माण हेतु रु0 5.00 करोड़
- विदेश रोजगार प्रकोष्ठ हेतु रु0 3.73 करोड़
- न्याय पंचायत स्तर पर स्टेडियम हेतु रु0 10.00 करोड़
- वन विभाग के अंतर्गत रेस्क्यू सेंटर हेतु रु0 19.00 करोड़

ज्ञान (GYAN)

- 'G' अर्थात् गरीब कल्याण
- 'Y' अर्थात् युवा
- 'A' अर्थात् अन्नदाता
- 'N' अर्थात् नारी सशक्तिकरण



गरीब कल्याणः मानव सेवा नारायण सेवा



- अन्नपूर्ति योजना- रु0 1300 करोड़
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) रु0 298.35 करोड़
- प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (शहरी) रु0 56.12 करोड़
- ई.डब्ल्यू.एस. आवास हेतु अनुदान- रु0 25.00 करोड़
- परिवहन निगम की बसों में निर्धारित श्रेणी के यात्रियों हेतु निःशुल्क यात्रा की सुविधा- रु0 42.00 करोड़
- निर्धन परिवार हेतु रसोई गैस पर अनुदान- रु0 43.03 करोड़
- दिव्यांग पेंशन, तीलू रौतेली पेंशन, बौना पेंशन एवं जन्म से 18 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों हेतु - रु0 167.05 करोड़
- दैवीय आपदाओं से प्रभावित परिवारों का पुनर्वासि- रु0 25.00 करोड़
- राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण- रु0 01.00 करोड़

युवा कल्याणः युवाओं को सशक्त बनाना

- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु- ₹ 60.00 करोड़
- मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना हेतु- ₹ 10.00 करोड़
- पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हेतु- ₹ 62.29 करोड़
- गैर-सरकारी महाविद्यालयों को सहायता अनुदान- ₹ 155.38 करोड़
- शिक्षा मित्रों को मानदेय का भुगतान- ₹ 10.00 करोड़
- मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना- ₹ 10.00 करोड़
- उल्लास - नव भारत साक्षरता कार्यक्रम- ₹ 3.34 करोड़

अन्नदाता

- द्राउट प्रोत्साहन योजना हेतु- रु0 39.90 करोड़
- आईटीबीपी बटालियन को जीवित भेड़, बकरी और कुक्कुट आपूर्ति योजना हेतु- रु0 3.50 करोड़
- दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनांतर्गत- रु0 42.50 करोड़
- हाउस ऑफ हिमालयाज के अन्तर्गत- रु0 05.00 करोड़
- मिशन एप्पल योजना अन्तर्गत समग्र रूप से - रु0 42.00 करोड़
- दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना हेतु समग्र रूप- रु0 32.00 करोड़
- मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजनांतर्गत- रु0 20.00 करोड़
- मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना हेतु- रु0 12.43 करोड़
- मिलेट मिशन योजना के प्रोत्साहन हेतु- रु0 12.00 करोड़
- स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन कार्यक्रम हेतु- रु0 5.75 करोड़
- मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना- रु0 20.00 करोड़
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना - रु0 160.13 करोड़
- गंगा कार्यकारी योजना के अन्तर्गत रखरखाव हेतु जल संस्थान को अनुदान- रु0 25.00 करोड़

नारी सशक्तिकरण

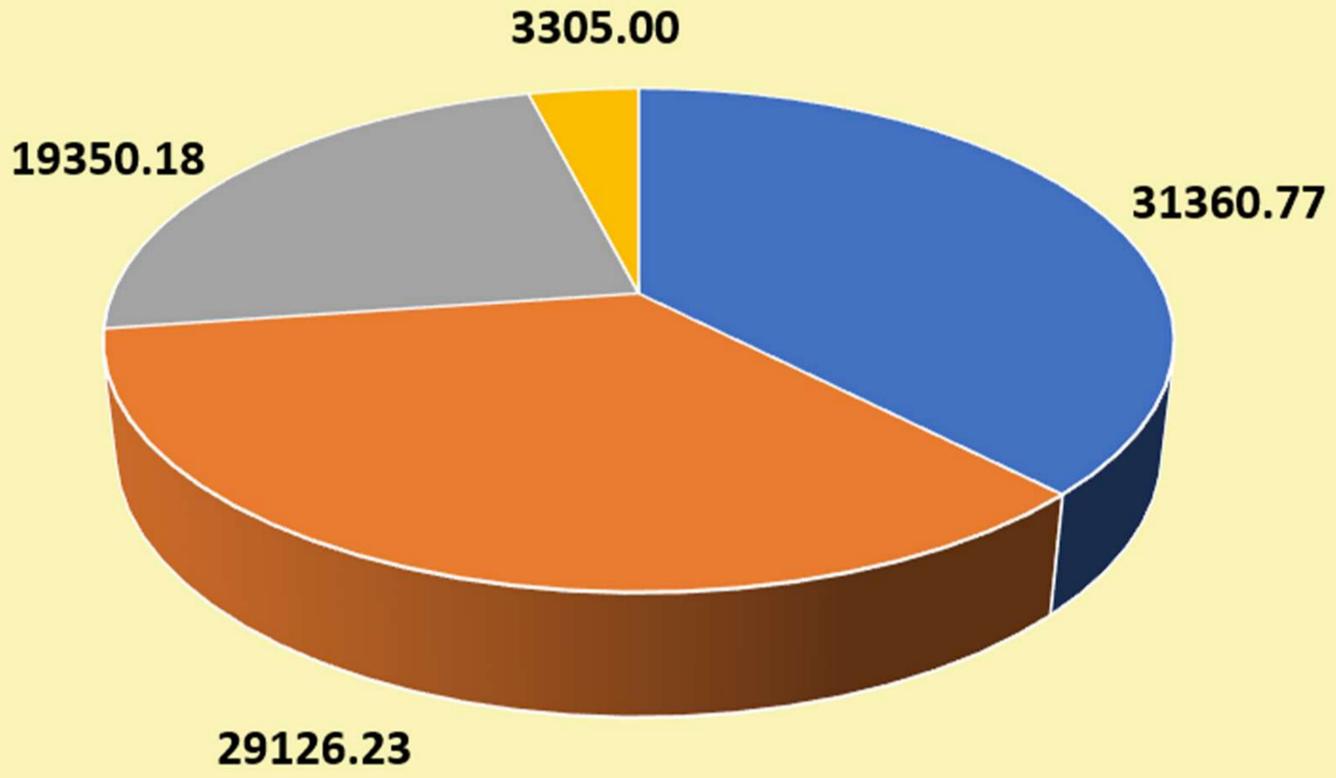


- नन्दा गौरा योजनांतर्गत- रु0 220.00 करोड
- प्रधानमंत्री मातृत्व वन्दना योजना- रु0 47.78 करोड
- मुख्यमंत्री बाल पोषण योजनांतर्गत- रु0 25.00 करोड
- मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजनांतर्गत- रु0 30.00 करोड
- मुख्यमंत्री महिला पोषण योजनांतर्गत- रु0 13.44 करोड
- मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजनांतर्गत- रु0 15.00 करोड
- मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि हेतु- रु0 08.00 करोड
- निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु- रु0 05.00 करोड
- मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत- रु0 3.76 करोड
- मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना हेतु- रु0 05.00 करोड
- राज्य में प्रसूता के लिए ईजा-बोर्ड शगुन योजना हेतु समग्र रूप से- रु0 14.13 करोड
- मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजनांतर्गत- रु0 02.00 करोड
- महिला स्पोर्ट्स कॉलेज चंपावत का निर्माण- रु0 10.00 करोड
- गंगा गाय महिला डेरी विकास योजनांतर्गत- रु0 05.00 करोड

सेक्टरवार स्थिति



आय-व्ययक अनुमान 2026-2027



■ सामान्य सेवायें ■ सामाजिक सेवायें ■ आर्थिक सेवायें ■ स्थानीय निकायों को अनुदान



राज्य की अर्थव्यवस्था



राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (State GSDP)

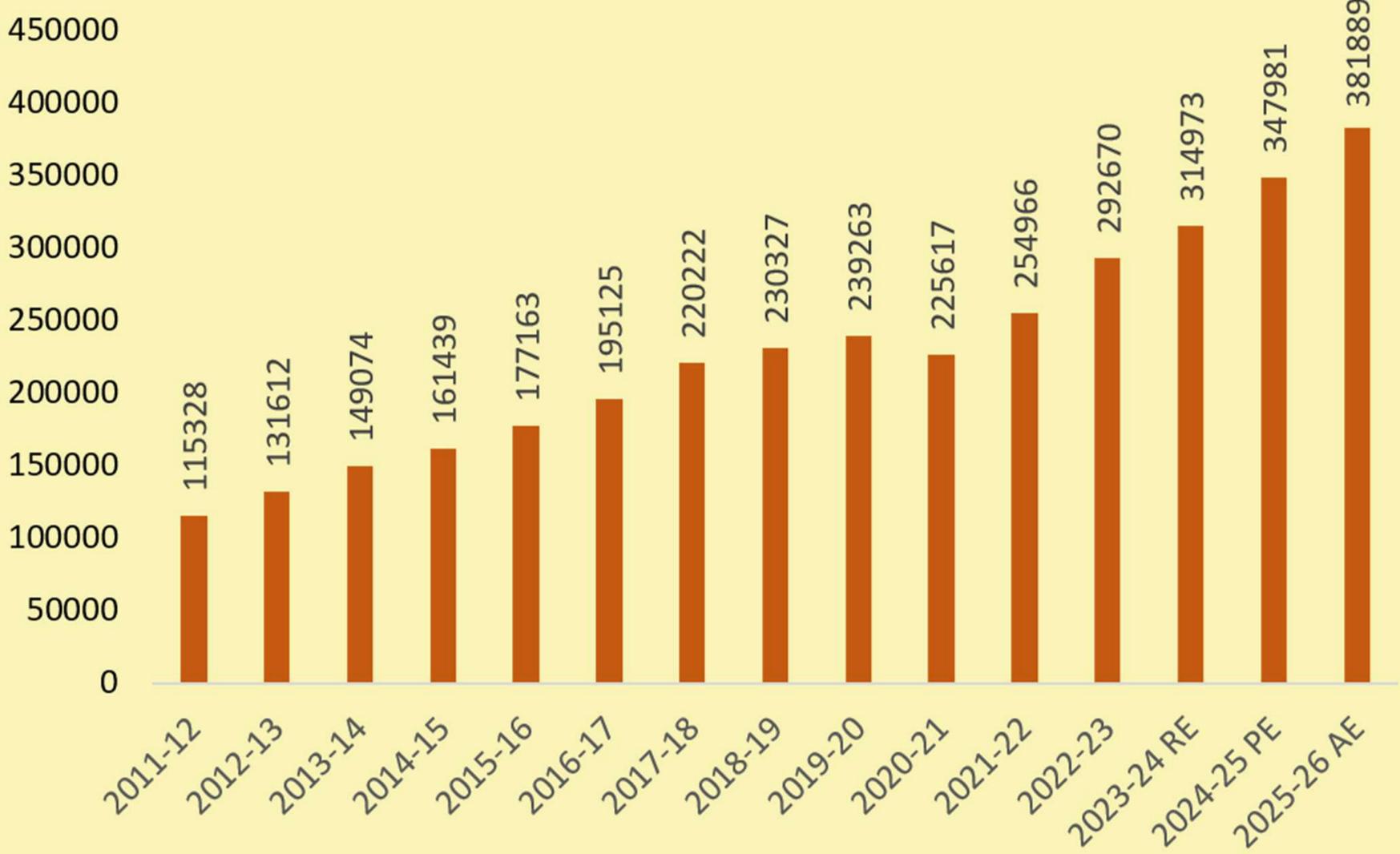
प्रचलित भावों पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद (करोड़ ₹ में)

वर्ष 2024-25 में

₹ 03 लाख 47 हजार करोड़

वर्ष 2025-26 में

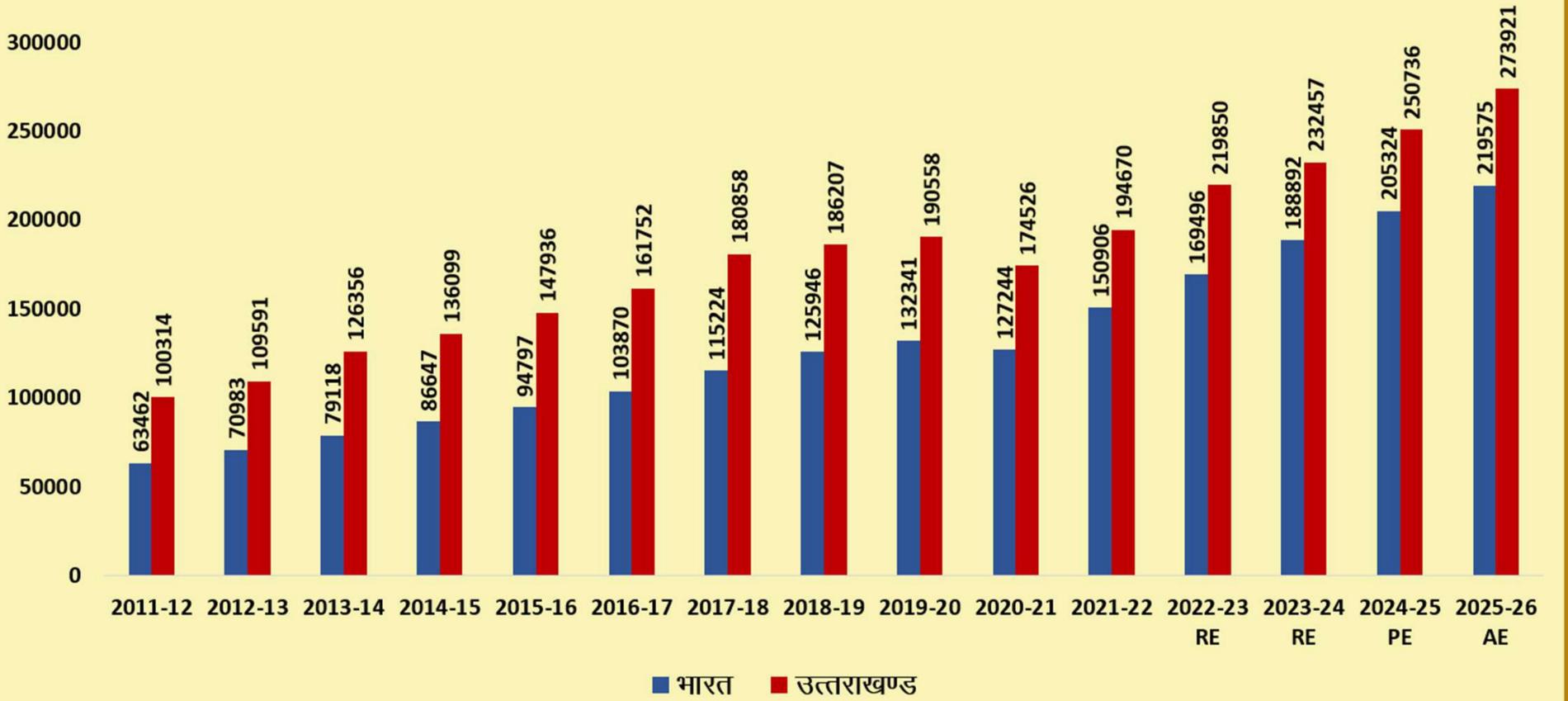
₹ 03 लाख 81 हजार करोड़



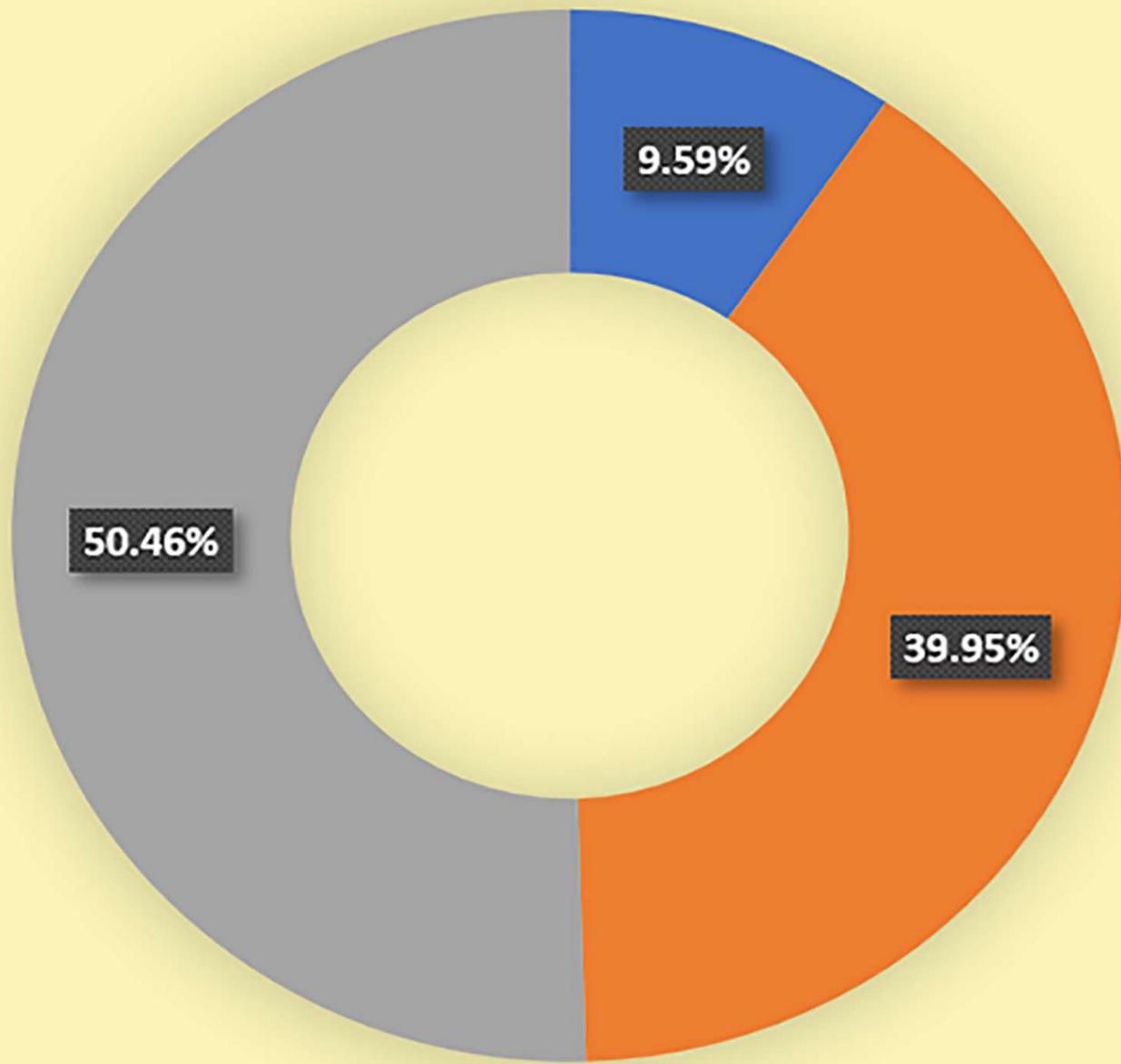
राज्य की अर्थव्यवस्था



प्रति व्यक्ति आय का तुलनात्मक ग्राफ



राज्य की अर्थव्यवस्था के घटक 2025-26 AE



■ प्राथमिक क्षेत्र ■ द्वितीयक क्षेत्र ■ तृतीयक क्षेत्र

